Demand to formulate comprehensive action plan to solve problems being faced by minorities in the country

श्री साबिर अली (बिहार) : सभापति जी, अल्पसंख्यकों के लिए पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का वांछित लाभ अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जब तक संवैधानिक दर्ज़ा नहीं दिया जाता, तब तक इसका वजूद सार्थक नहीं होगा। वक्फ कानून 1995 में बहुत से संशोधन होने हैं, जो काफी समय से लंबित हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का कार्य संतोषजनक नहीं है। इसके द्वारा उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा इसकी प्रक्रिया जटिल है और पारदर्शी भी नहीं है। इसमें फंड भी कम है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को और अधिक पैसा दिए जाने की जरूरत है। सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल को भी मज़बूत करने की जरूरत है। मुस्लिम इलाकों में और अधिक स्कूल और कालेज खोले जाने की जरूरत है। वक्फ कमेटी की सिफारिशों पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट बढ़ाकर पांच गुना करने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों को सही मायने में सुरक्षा प्रदान किए जाने की जरूरत है।

सभापति जी, सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अब तक कोई खास अमल नहीं किया गया है, उनको जल्दी लागू किया जाना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसमें की गई सिफारिशों को लागू किया जाए। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात अभी भी बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हज और मुस्लिम शिक्षा, जो कि केवल मुसलमानों से संबंधित है, ये विषय दूसरे मंत्रालयों के पास हैं, इनको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए। मुस्लिम इलाकों में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाए और इनको शीघ्रातिशीघ्र लागू करे।

Demand to revise NREGA scheme to increase the working days and the wages

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, the National Rural Employment Guarantee Programme of the UPA Government is a unique scheme which has given employment to nearly four crores of rural poor in India. But the Scheme ensures 100 days' employment, which is not adequate for a poor labour family. The guaranteed days of employment should be increased to 240 working days. The minimum wages of NREGA workers should be increased and the rate and measurement of price-related contract work should also be revised as a NREGA worker is not getting the minimum wages as per the old measurement.

The Government should also start new National Employment Guarantee Scheme for urban poor and employment and self-employment schemes for non-matric, matric, intermediate, graduate, post-graduate and non-technical students who can neither do the hard physical work nor can they do the technical jobs. Their number is much more and they are the real problems for everybody.

All NREGA workers should get rice and wheat at a subsidized rate *i.e.* @ Rs.2/- per kg. All NREGA workers should be covered under *Aam Aadmi Bima Yojana* and also should get free medical care and creche facility at the work place.

MR. CHAIRMAN: Dr. Najma A. Heptulla.